पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

वसीम एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2016 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1099

07 अप्रैल 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह और माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ताओं द्वारा हत्या के आरोप को स्थापित करने के लिए विश्वसनीय, पर्याप्त और ठोस साक्ष्य मौजूद हैं, टिकने योग्य है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872---धारा 118---हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील----बाल साक्षी की गवाही---परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन।

माना गया:- घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह घटना के समय लगभग पाँच वर्ष का था और उसकी गवाही दर्ज किए जाने के समय उसकी आयु आठ वर्ष थी---बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि बाल साक्षी आसानी से बहकावे में आ सकता है---एल.डी. बाल गवाह की गवाही दर्ज करते समय, ट्रायल कोर्ट को इस आशय की संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता होती है कि नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है, जो बदले में पूछे गए प्रश्नों का तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है --- हालांकि, वर्तमान मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस गवाह की क्षमता का आकलन करने के लिए बाल गवाह से कोई भी प्रश्न पूछने का कष्ट नहीं किया है, न ही उसके बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान कहीं भी गवाह के किसी भी व्यवहार को रिकॉर्ड किया गया है --- बाल गवाह अपने संस्करण में सुसंगत नहीं था और यह विसंगतियों, अतिशयोक्ति और अलंकरणों से भरा हुआ है और इसलिए अविश्वसनीय है --- कथित अपराध के प्रत्यक्षदर्शी

गवाह की अनुपस्थिति में, अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता को स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य आवश्यक हो जाता है --- परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं कि जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाता है, उन्हें दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए और संदेह के लिए खुला नहीं होना चाहिए और इसे बिना किसी अंतराल के अपराध के साथ अभियुक्त को जोड़ते हुए एक पूरी श्रृंखला बनानी चाहिए विसंगतियां---वर्तमान मामले में, मृतक पर हमला करने और उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया गया खंजर/चाकू पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया गया है, न ही खून से लथपथ मिट्टी/कपड़े जब्त किए गए हैं, और न ही एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं, न ही घटना का मकसद स्थापित किया गया है, न ही जांच रिपोर्ट/पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित की गई है और न ही फर्दबयान पेश किया गया है, सिवाय इस तथ्य के कि अभियोजन पक्ष जांच अधिकारी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करने में विफल रहा है---- जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना था, वे वर्तमान मामले में मौजूद नहीं हैं, इसलिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाते हैं कि अपीलकर्ताओं ने अपराध किया है---दोषी ठहराए जाने का विवादित फैसला खारिज किया गया---अपीलकर्ताओं को बरी किया गया----अपील स्वीकार की गई। (पैरा-16-17, 19-22)

न्याय दृष्टान्त

भगवान सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2003) 3 एससीसी 21; पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एससीसी 177; दिगम्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2019)4 एससीसी 522; प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 777 .....पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 374(2), 389(1)---भारतीय दंड संहिता---302, 34--- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872---धारा 118

मुख्य शब्दों की सूची

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---हत्या---प्रत्यक्षदर्शी----बाल गवाह की गवाही----परिस्थितिजन्य साक्ष्य---संदेह का लाभ।

प्रकरण से उत्पन्न

सत्र परीक्षण संख्या 817/2011 में अपर सत्र न्यायाधीश-II, बेगूसराय के विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 6.9.2016 और 08.9.2016 को दोषसिद्धि और सजा का आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: सुश्री मीरा कुमारी, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं की ओर से: सुश्री शशि बाला वर्मा, एपीपी
हेडनोट बनाया गया: घनश्याम

उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 1099

थाना कांड संख्या-43 वर्ष-2011 थाना- खोदावंदपुर जिला- बेगूसराय से उत्पन्न

==========

1. मोहम्मद वसीम, पिता- मोहम्मद इजहारुल हक उर्फ मोहम्मद इजहारुल
2. नूरजहाँ, पति- मोहम्मद इजहारुल हक उर्फ मोहम्मद इजहारुल दोनों निवासी- नुरुल्लाहपुर, थाना-खोदावंदपुर, जिला-बेगूसराय

... ...अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ...उत्तरवादी

==========

उपस्थितिः-

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : सुश्री मीरा कुमारी, अधिवक्ता

उत्तरवादी /ओं की ओर से : सुश्री शशि बाला वर्मा, स.लो. अ.

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

तारीखः 07.04.2025

वर्तमान अपील धारा 374(2) सहपठित धारा 389(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'दं.प्र.सं. ' कहा जाएगा) के अंतर्गत अपीलकर्ताओं द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश-II, बेगूसराय (जिसे आगे विद्वान विचारण न्यायाधीश कहा जाएगा) के विद्वान न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 817/2011 (खोदावंदपुर पी.एस. केस संख्या 43/2011 से उत्पन्न) में दिनांक 6.9.2016 और 08.9.2016 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 06.09.2016 के उक्त निर्णय द्वारा, उपरोक्त अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (जिसे आगे 'भ. दं. सं. ' कहा जाएगा) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें भ. दं. सं. की धारा 34 के साथ धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक पर 25,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मो. सलीम का *फर्दबयान* खोदावंदपुर थाना के थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 25.03.2011 को रात्रि 10:00 बजे घर पर दर्ज किया गया। अपने *फर्दबयान* में सूचक अर्थात मो. सलीम ने कहा है कि दिनांक 25.03.2011 को

लगभग 05:00 बजे शाम में उनकी पत्नी अजरुल खातून अपने छोटे पुत्र सहनवाज (अ. सा.-5) के साथ किसी काम से उत्तरी छोर पर स्थित अपने खेत में गयी थी कि उसी समय उसके पड़ोसी मो. वसीम (अपीलार्थी संख्या 1) की बकरी और उसका बच्चा सूचक के खेत में घुस आया, जिस पर उसकी पत्नी ने फसल बचाने के उद्देश्य से बकरी और उसके बच्चे को वहां से भगा दिया। उस समय मो. वसीम जो उस स्थान पर अपनी बकरी चरा रहा था, ने सूचक की पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाया, जिसके बाद मो. वसीम अपने घर चला गया और फिर सूचक की पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ खेत से वापस आने लगी, लेकिन जैसे ही वह *बाँध* के पास पहुंची, मो. वसीम (अपीलार्थी संख्या 1) अपने हाथ में बकरी काटने वाला चाकू (क्लीवर) लेकर अपनी मां नूरजहां (अपीलार्थी संख्या 2) के साथ सूचक की पत्नी के पास आ गया, नूरजहां ने मो. वसीम को उकसाया जिसके फलस्वरूप मो. वसीम ने सूचक की पत्नी के गर्दन पर वार कर दिया जिससे उसके बाएं कंधे पर हाथ के पास चोट लग गई तथा काफी खून बहने लगा। सूचक ने आगे बताया कि शोर सुनकर वह और उसकी बड़ी बेटी दौड़कर *बाँध* पर गए जहां देखा कि उसकी पत्नी खून से लथपथ थी तथा दर्द से छटपटा रही थी। इसके बाद सूचक किसी तरह अपनी पत्नी को घर ले आया तथा जब वे उसे इलाज के लिए रोसड़ा ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचक ने यह भी बताया कि मो. वसीम द्वारा उसकी पत्नी के बाएं हाथ पर खंजर से वार करने के कारण काफी खून बहने के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। सूचक का फर्दबयान सूचक को पढ़कर सुनाया गया जिसे उसने समझ लिया था तथा सही पाकर उस पर अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाया था। *फर्दबयान* दर्ज होने के बाद 26.03.2011 को रात्रि 00:30 बजे उक्त अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड

संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 43/2011 के तहत औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई।

3. जांच के बाद और अपीलकर्ता संख्या 2 के विरुद्ध मामले को सही पाते हुए, पुलिस ने 30.07.2011 को भ. दं. सं. की धारा 302/34 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया था और उसके बाद अपीलकर्ता संख्या 1 के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया था। तब विद्वान विचारण न्यायालय ने भ. दं. सं. की धारा 302/34 के तहत अपराध का संज्ञान लिया था, जिसके बाद मामला 06.09.2011 के आदेश के तहत सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था और इसे सत्र परीक्षण संख्या 817/2011 के रूप में क्रमांकित किया गया था। आरोप पत्र और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने 19.09.2012 को अपीलकर्ता संख्या 2 के खिलाफ और 21.10.2011 को अपीलकर्ता संख्या 1 के खिलाफ भ. दं. सं. की धारा 302/34 के तहत आरोप तय किए। यद्यपि उपरोक्त दोनों अपीलकर्ताओं के मुकदमों को अलग कर दिया गया था, किन्तु बाद में दोनों को वर्तमान सत्र मुकदमों संख्या 817/2011 में समाहित कर दिया गया।

4. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के 5 गवाहों से पूछताछ की गई, यानी अ. सा.-1 मोजीबुर रहमान, जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है, अ. सा.-2 मोहम्मद सलीम (इस मामले के सूचक और मृतक अजरुल खातून के पति), अ. सा.-3 फरहत परवीन (मृतक की बेटी), अ. सा.-4 जसिमा खातून (मृतक की भाभी) और अ. सा.-5 मोहम्मद साहनवाज (मृतक का बेटा)।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील मीरा कुमारी ने समर्पित किया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही, घटना के स्थान और घटना के तरीके

के संबंध में विरोधाभास और असंगति से भरी हुई है। यह भी तर्क किया गया है कि न तो *फर्दबयान* प्रस्तुत किया गया है, न ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इस तथ्य के अलावा कि कथित घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद नहीं किया गया है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि न तो जांच अधिकारी और न ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की जांच की गई है, जिससे अपीलकर्ताओं को गंभीर नुकसान हुआ है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***राजेश पटेल बनाम झारखंड राज्य; (2013)3 एससीसी 791,*** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा का निर्णय विरोधाभासी है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

6. *इसके विपरीत,* राज्य के विद्वान स.लो. अ. , सुश्री शशि बाला वर्मा ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों यानी अ. सा.-2 से अ. सा.-5 ने लगातार यह बयान दिया है कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने मृतका पर चाकू से वार किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की लगातार गवाही के मद्देनजर, जांच अधिकारी और डॉक्टर की गैर-परीक्षा अपीलकर्ताओं के लिए किसी भी पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनेगी, इसलिए विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, दोषसिद्धि के फैसले और विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए सजा के आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है, इस प्रकार वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के अलावा हमने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया है। आगे बढ़ने से पहले साक्ष्यों पर सरसरी तौर पर चर्चा करना जरूरी है।

8. अ. सा.-1, मोजीबुर रहमान ने अपने बयान में कहा है कि उसे घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसने पुलिस के समक्ष कोई बयान भी नहीं दिया है, इसलिए अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उसके साक्ष्य पर चर्चा करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

9. अ. सा.-2, मो. सलीम इस मामले के सूचक हैं तथा मृतक अजरूल खातून के पति हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि घटना तीन वर्ष पूर्व शाम लगभग 05:00 बजे की है, जब उनकी पत्नी अजरूल खातून खेत से काम करके लौट रही थी और जब वह नूरुल्लाहपुर गांव के *बाँध* के पास पहुंची तो नूरजहां से झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसने उसे खंजर से मार डालने का आह्वान किया, जिसके कारण मो. वसीम (अपीलार्थी संख्या 1) ने मृतक के गले पर खंजर से वार किया, जो उसके हाथ और कंधे पर लगा, जिससे वह बेहोश हो गई तथा काफी खून बहने लगा, फिर उसे इलाज के लिए रोसड़ा ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अ. सा.-2 ने आगे कहा है कि घटना को बेटी फरहत परवीन (अ. सा.-3), बेटे मोहम्मद साहनवाज (अ. सा.-5) और उसकी साली यानी कमरुलजमा की पत्नी ने देखा था। पैराग्राफ संख्या 3 में अ. सा.-2 ने कहा है कि वह पुलिस स्टेशन गया था, जहां उसका बयान दर्ज किया गया था। अ. सा.-2 ने कटघरे में खड़े अपीलकर्ताओं को भी पहचाना था। पैराग्राफ संख्या 5 में अ. सा.-2 ने कहा है कि उसकी बकरी वसीम के खेत में भटक गई थी, जिसके बाद बकरी को भगा दिया गया, जिसके कारण यह घटना घटी। अपनी जिरह में अ. सा.-2 ने कहा है कि शोर सुनकर वह

और उसकी बेटी वहां गए और देखा कि उसकी पत्नी खून से लथपथ थी और दर्द से कांप रही थी, जिसके बाद वे उसे इलाज के लिए रोसड़ा ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अ. सा.-2 ने घटनास्थल का भी वर्णन किया है, जहां *मसूर* और गेहूं की फसलें उगी हुई हैं। उसने यह भी कहा है कि मो. वसीम का घर उसके घर से थोड़ी दूरी पर है। अपनी जिरह के पैरा संख्या 8 में अ. सा.-2 ने कहा है कि उसकी पत्नी पहले अकेली खेत में गई थी। उसने यह भी कहा है कि उसने अपनी पत्नी को गंडक नदी के किनारे *बाँध* के नीचे खून से लथपथ देखा था। अपनी जिरह के पैरा संख्या 9 में अ. सा.-2 ने कहा है कि वह यह नहीं बता सकता कि जब उसने अपनी पत्नी को उठाया और वापस लाया तो कितने लोग मौजूद थे। उसने यह भी कहा है कि उसके और उसकी बेटी के कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे, हालांकि पुलिस कर्मियों ने कपड़े नहीं लिए थे। अ. सा.-2 ने यह भी कहा है कि जब वे उसकी पत्नी को इलाज के लिए रोसड़ा ले जा रहे थे और हटिया गांव पहुंचे थे, तब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वे अपने घर वापस आ गए थे, जहां पुलिस कर्मी लगभग 6:00 बजे पहुंचे थे और फिर वे 2 दिनों के बाद आए थे।

10. अ. सा.-3, फरहत परवीन मृतक की पुत्री है और उसने अपने बयान में कहा है कि घटना तीन वर्ष पूर्व शाम लगभग 5:00 बजे की है जब वह अपने घर पर थी। उसने यह भी कहा है कि बकरी द्वारा खेत चरने के कारण अपीलकर्ताओं और उसकी मां अजरुल खातून के बीच झगड़ा हुआ और फिर नूरजहां ने कहा कि अजरुल खातून को मार दिया जाना चाहिए क्योंकि वह हर दिन झगड़ा करती है। अ. सा.-3 ने आगे कहा है कि उसकी मां खेत में गई थी और मो. वसीम (अपीलकर्ता संख्या 1) ने उसकी मां पर खंजर से वार किया, जिसे उसने अपने हाथ से पकड़ लिया और फिर खंजर उसकी छाती में जा लगा। उसने यह भी कहा है कि वे उसकी मां को इलाज के लिए रोसड़ा ले गए थे, हालांकि,

रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वे शव को वापस अपने घर ले आए थे। उसने यह भी कहा है कि घटना बंद के नीचे हुई थी। उसने कटघरे में खड़े अपीलकर्ताओं को पहचान लिया है। जिरह में अ. सा.-3 ने कहा है कि उसका बयान पुलिस ने दर्ज किया है, जिसमें उसने कहा है कि हो-हल्ला मचाया गया कि मो. वसीम ने उसकी मां पर चाकू से वार किया है, जिसके बाद वह दौड़कर वहां पहुंची तो देखा कि उसकी मां घायल अवस्था में गिरी हुई है। उसने यह भी कहा है कि उसके घर और *बाँध* के बीच नीचे की तरफ 50-60 फीट की दूरी है और जिस खेत में घटना हुई, वह *बाँध* के दक्षिण दिशा में है और उस समय खेत में गेहूं की फसल उग रही थी। उसने यह भी कहा है कि उसके पिता उसकी मां को उठाकर लाए थे, लेकिन जब वे उसे इलाज के लिए रोसड़ा ले जा रहे थे, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

11. अ. सा.-4, जसिमा खातून मृतक की भाभी है और उसने अपने बयान में कहा है कि घटना तीन साल और कुछ महीने पहले की है जब वह अपने घर के आंगन में थी और *शोर* सुनकर वह बाहर आई और देखा कि मोहम्मद वसीम अपनी मां के साथ खंजर लेकर घटनास्थल की ओर जा रहा था और अपीलकर्ता नंबर 2 कह रही थी कि वह उसे नहीं छोड़ेगी और साथ ही अजरुल खातून को गाली दे रही थी। अजरुल खातून ने तब वसीम की बकरी को अपने खेत से भगा दिया था। अ. सा.-4 ने अपने मुख्य परीक्षण के पैराग्राफ नंबर 2 में कहा है कि वसीम खंजर लेकर खेत में गया था और उसने अजरुल खातून पर खंजर से हमला किया था जो उसके गले के पास लगा था और फिर वह नदी की ओर भाग गया था। उसने यह भी कहा है कि उन्होंने तब मृतक को उठाया और उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए, हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जिरह में अ. सा.-4 ने कहा है कि उसका और मृतका का आंगन एक ही है, लेकिन वे अलग-अलग

रहते हैं। उसने यह भी कहा है कि उसका और वसीम का घर एक दूसरे से सटा हुआ है और आरोपी और सूचक के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। अपनी जिरह के पैराग्राफ संख्या 4 में उसने यह भी कहा है कि साहनवाज ने बताया था कि उसकी मां की हत्या कर दी गई है। अ. सा.-4 ने आगे कहा है कि जब वह घटनास्थल पर गई थी, तो मृतका अजरुल खातून दर्द से कराह रही थी और वहां कुछ लोग भी मौजूद थे। अ. सा.-4 ने आगे कहा है कि उसने कहा था कि वसीम अपनी मां के साथ हाथ में खंजर लेकर जा रहा था और वे अजरुल खातून को गाली दे रहे थे और उसने यह भी कहा था कि वसीम और उसकी मां *बाँध* के पास गए थे, जहां वसीम ने खंजर से हमला किया जो उसकी मां के गले के पास लगा और उसके बाद अपीलकर्ता भाग गए थे। अ. सा.-4 ने भी अपनी जिरह में घटनास्थल का वर्णन किया है।

12. अ. सा.-5 मो. सहनवाज मृतक का पुत्र है, जो कथित घटना के समय लगभग पांच वर्ष का था। उसने अपने बयान में कहा है कि उसकी मां का नाम अजरुल खातून है जो मर चुकी है और मो. वसीम ने उसकी छाती में खंजर घुसा दिया था क्योंकि उसकी बकरी उसके खेत की फसल चर गई थी। उसने कटघरे में खड़े अपीलकर्ताओं को पहचान लिया था। जिरह में उसने कहा है कि वह थाने के प्रभारी अधिकारी से अपने घर पर मिला था। उसने यह भी कहा है कि जिस समय वह प्रभारी अधिकारी से मिला था, उस समय उसकी मां का शव घर पर पड़ा था और प्रभारी अधिकारी ने उससे पूछताछ की थी और उसे बताया था कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। पैराग्राफ क्रमांक जिरह के दौरान अ. सा.-5 ने बताया कि उसके घर में दो कमरे हैं और जब वह अपने घर के कमरे से बाहर आया तो उसने अपनी मां का शव देखा।

13. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद करने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने 30.06.2016 को दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं के बयान दर्ज किए ताकि वे उनके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कर सकें, हालांकि, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया।

14. विचारण न्यायालय ने विचारण में प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन, विश्लेषण और जांच के पश्चात उपरोक्त अपीलकर्ताओं को अपराध का दोषी पाया है तथा अपने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उन्हें कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

15. हमने विद्वान ट्रायल कोर्ट के विवादित फैसले, रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सामग्रियों का अवलोकन किया है और अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान स.लो. अ. द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है। अ. सा.-2, यानी सूचना देने वाले के साक्ष्य का एक मात्र अवलोकन यह दिखाएगा कि उसके जिरह के पैराग्राफ संख्या 8 में, उसने कहा है कि उसकी पत्नी अकेले खेत में गई थी और उसने अपनी पत्नी को गंडक नदी के किनारे *बाँध* के नीचे लेटा हुआ देखा था, इसलिए, जाहिर है, उसे प्रत्यक्षदर्शी नहीं कहा जा सकता है। जहां तक अ. सा.-3, फरहत परवीन का सवाल है, उसने जिरह के पैरा 4 में कहा गया है कि जब हल्ला मचा कि मोहम्मद वसीम ने उसकी मां पर खंजर से हमला किया है, तो वह भागकर घटनास्थल पर गई, जहां उसने पाया कि उसकी मां घायल अवस्था में गिरी हुई थी, इस प्रकार अ. सा.-3 भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अ. सा.-4, जसिमा खातून के संबंध में, उसके साक्ष्य का केवल अवलोकन, विशेष रूप से उसके जिरह के पैरा 4 से पता चलता है कि जब वह घटनास्थल पर गई थी, तो अजरुल खातून दर्द से कांप रही थी और कुछ लोग वहां खड़े थे, इस प्रकार, जाहिर है, वह भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

वास्तव में फर्दबयान में भी, सूचक (अ. सा.-2) यह दावा नहीं करता है कि उसने और उसकी बेटी (अ. सा.-3) ने मोहम्मद वसीम द्वारा मृतक पर खंजर से वार करने की वास्तविक घटना देखी थी। अब हमारे पास अ. सा.-5 मो. साहनवाज (मृतका का पुत्र) की गवाही बची है, जिसने अपनी जिरह के पैरा संख्या 5 में कहा है कि जब वह कमरे से बाहर आया तो उसने अपनी मां का शव घर के रास्ते में पड़ा हुआ पाया, इसलिए उसे भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं कहा जा सकता।

16. मामले का एक और पहलू यह है कि अ. सा.-5, मोहम्मद सहनवाज, जो एकमात्र चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है, घटना के समय लगभग पांच साल का था और उसकी गवाही दर्ज किए जाने के समय आठ साल का था। इस संबंध में यह समझना आवश्यक होगा कि एक बाल गवाह की गवाही को कैसे देखा और सराहा जाना चाहिए, क्योंकि अदालत का यह देखना और विश्लेषण करना बाध्यकारी कर्तव्य है कि क्या ऐसे गवाह का सबूत ठोस और विश्वसनीय है या क्या गवाह को समझाने की पर्याप्त गुंजाइश थी। बाल गवाह की गवाही के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***भगवान सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य; (2003) 3 एससीसी 21;*** के मामले में बाल गवाह की योग्यता को ध्यान में रखा है और माना है कि बाल गवाह की एकमात्र गवाही पर भरोसा करना खतरनाक होगा, यदि घटना के तुरंत बाद उसे प्रशिक्षित करने की संभावना नहीं है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 और 22 नीचे उद्धृत हैं:-

> *"19. कानून बच्चे को एक सक्षम गवाह के रूप में मान्यता देता है, लेकिन एक बच्चा, विशेष रूप से छह वर्ष की इतनी कम उम्र में, जो अपरिपक्व समझ के कारण घटना की प्रकृति के बारे में उचित राय बनाने में असमर्थ है, उसे अदालत द्वारा गवाह नहीं माना जाता है,*

जिसकी एकमात्र गवाही पर अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना भरोसा किया जा सकता है। बच्चे के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है क्योंकि वह आसानी से बहकावे में आ सकता है। इसलिए, अदालत हमेशा उसकी गवाही के लिए अन्य साक्ष्यों से पर्याप्त पुष्टि की तलाश करती है, (देखें पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1998) 7 एससीसी 177]।

22. बच्चे के गवाह की एकमात्र गवाही पर भरोसा करना खतरनाक है क्योंकि यह घटना के तुरंत बाद और उसे प्रशिक्षित करने और पढ़ाने की किसी भी संभावना से पहले उपलब्ध नहीं है। (देखें असम राज्य बनाम मार्फिन अहमद [(1983) के पैरा 14-15) 2 एससीसी 14]। उस मामले में एक बाल गवाह के साक्ष्य की सराहना की गई और उसे अविश्वसनीय माना गया (एससी पृष्ठ 20)

> *14. दूसरा प्रत्यक्ष साक्ष्य मृतक के बेटे अ. सा.- 7 का बयान है, जो 7 साल का एक बालक है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है:*
>
> *'...एक बाल गवाह का साक्ष्य हमेशा खतरनाक होता है जब तक कि यह घटना के तुरंत बाद और कोचिंग और ट्यूशन की किसी भी संभावना से पहले उपलब्ध न हो। '*
>
> *15. अ. सा.- 7 के बयान का एक मात्र अवलोकन हमें आश्वस्त करता है कि वह पूरे समय झिझक रहा था और उसने अपने नाना या अपने चाचा द्वारा कहे गए बयान के अनुसार ही बयान दिया है। यह सच है कि हम इस गवाह के बयान में बहुत अधिक निरंतरता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो केवल 7 साल का बालक था। लेकिन उसके बयान के लहजे से यह स्पष्ट है कि वह एक स्वतंत्र एजेंट नहीं था और उसे सभी चरणों में किसी न किसी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। ”*

17. बाल गवाह के साक्ष्य के साक्ष्य मूल्य पर ***पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** के मामले में भी विचार किया गया था, जिसकी रिपोर्ट ***(1998)7 एससीसी 177*** में दी गई थी, जिसमें यह माना गया था कि बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि बाल गवाह ट्यूटरिंग का आसान शिकार होता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 11 और 12 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

> *"11.....कानून कहता है कि बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन बहुत सावधानी से और अधिक सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा दूसरों की बातों से प्रभावित होने के लिए अतिसंवेदनशील होता है और इस प्रकार एक बाल गवाह आसानी से बहकावे में आ जाता है।*
> *12. न्यायालयों ने निर्धारित किया है कि बाल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले उसे पर्याप्त पुष्टि मिलनी चाहिए। यह कानून से अधिक व्यावहारिक ज्ञान का नियम है। "*

18. हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिगम्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य; (2019)4 एससीसी 522;** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए, उसी के पैराग्राफ संख्या 21 और 22 को उद्धृत कर सकते हैं:-

> *"21. अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से बाल गवाह चांदनी की गवाही पर निर्भर है, जिसकी अ. सा.- 8 के रूप में जांच की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 गवाही देने वाले व्यक्तियों की योग्यता को नियंत्रित करती है जिसमें बाल गवाह भी शामिल है। बाल गवाह का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर हो सकती है। व्यवहार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर मामले में बाल गवाह के साक्ष्य को अन्य साक्ष्यों से पुष्ट किया जाना चाहिए, तभी दोषसिद्धि की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन विवेक के तौर पर अदालत हमेशा रिकॉर्ड पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से ऐसे साक्ष्य की पुष्टि करना वांछनीय समझती है।*

बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय अदालत को केवल एक सावधानी बरतनी चाहिए कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए।

22. इस न्यायालय ने लगातार माना है कि बाल गवाह के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित हो सकता है और वह आसानी से बहकावे में आ सकता है इसलिए, बाल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले उसे पर्याप्त पुष्टि मिलनी चाहिए। यह कानून से अधिक व्यावहारिक ज्ञान का नियम है। "

19. विद्वान ट्रायल कोर्ट को एक बाल गवाह की गवाही दर्ज करते समय इस आशय की संतुष्टि दर्ज करनी होती है कि नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है, जो बदले में पूछे गए प्रश्नों का तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। विद्वान ट्रायल कोर्ट की यह संतुष्टि कुछ प्रारंभिक प्रश्नों पर आधारित है, जो बाल गवाह से पूछे जाने चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि गवाह प्रश्नों को समझने में सक्षम है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के अनुसार कुछ हद तक तर्कसंगतता के साथ उनका उत्तर दे सकता है। इस संबंध में, हम ***प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का संदर्भ देना चाहते हैं, जो ***2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 777*** में रिपोर्ट किया गया है, जिसके पैराग्राफ संख्या 9, 10 और 11 नीचे दिए गए हैं:-

"9. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि बाल गवाह की गवाही की पुष्टि करना कोई नियम नहीं है, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है। कम उम्र के बाल गवाह को आसानी से सिखाया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में बाल गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। न्यायालय को इस प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि क्या बाल गवाह को सिखाया जा सकता है। इसलिए, न्यायालय द्वारा बाल गवाह के साक्ष्य की जांच सावधानी और सतर्कता के साथ की जानी चाहिए।

10. नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, न्यायिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है। न्यायाधीश को यह संतुष्ट होना चाहिए कि नाबालिग प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझता है। इसलिए, साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे नाबालिग से उचित प्रश्न पूछकर उसकी उचित प्रारंभिक जांच करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है या नहीं और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है या नहीं। प्रारंभिक प्रश्न और उत्तर रिकॉर्ड करना उचित है ताकि अपीलीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट की राय की सत्यता की जांच कर सके।

11. मामले के तथ्यों में नाबालिग की प्रारंभिक जांच बहुत ही अधूरी है। नाबालिग से केवल तीन प्रश्न पूछे गए, जिसके आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साक्षी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। इसलिए उसे शपथ दिलाई गई। उससे निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए:-

प्रश्न: आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं?

उत्तर: मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय, बड़वाशनी में पढ़ रहा हूं।

प्रश्न: आपके पिता का व्यवसाय क्या है?

उत्तर: मेरे पिता गोहनबा में हनुमान नामक मंदिर में पुजारी हैं।

प्रश्न: क्या सच बोलना चाहिए या झूठ?

उत्तर: सच"

20. हालाँकि, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने बाल गवाह यानी अ. सा.-5 से इस गवाह की क्षमता का आकलन करने के लिए कोई भी प्रश्न पूछने का कष्ट नहीं उठाया है, न ही उसके बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान गवाह के

किसी भी व्यवहार को कहीं भी रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार, हम इस निश्चित दृष्टिकोण से हैं कि विद्वान निचली अदालत ने प्रश्नों को समझने और तर्कसंगत उत्तर देने के लिए उक्त गवाह की क्षमता और योग्यता के संबंध में खुद को संतुष्ट नहीं किया है और यहां तक उसके बारे में संतुष्टि भी दर्ज नहीं की है, जिससे ऐसे गवाह की विश्वसनीयता पर संदेह करने की गुंजाइश बनी हुई है। जहां तक बाल गवाह यानी अ.सा.-5 के साक्ष्य की अधिक सावधानी से जांच करने का सवाल है, हम ट्रायल के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह गवाह अपने बयान में सुसंगत नहीं रहा है और यह असंगतियों, अतिशयोक्ति और अलंकरणों से भरा हुआ है। इस मामले को देखते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर अ. सा.-5 की गवाही अविश्वसनीय हो जाती है।

21. इस प्रकार हम वर्तमान मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से पाते हैं कि अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। इसलिए, कथित अपराध के प्रत्यक्षदर्शी गवाह की अनुपस्थिति में, अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता को स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य आवश्यक हो जाता है। यह एक सुस्थापित कानून है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं कि जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाता है, वे दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए और संदेह के लिए खुली नहीं होनी चाहिए, परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से अभियुक्त की भागीदारी की ओर इशारा करना चाहिए और वैकल्पिक स्पष्टीकरण के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए, परिस्थितियों को एक पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए, बिना किसी अंतराल या विसंगतियों के अभियुक्त को अपराध से जोड़ना चाहिए और परिस्थितियों को अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना द्वारा समझाया नहीं जाना चाहिए। अब

वर्तमान मामले पर वापस आते हुए, हम पाते हैं कि मृतक पर हमला करने और उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया गया खंजर/चाकू पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया गया है, न ही खून से लथपथ मिट्टी/कपड़े जब्त किए गए हैं, और न ही एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं, न ही घटना का मकसद स्थापित किया गया है, न ही जांच रिपोर्ट/पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित हुई है और न ही फर्दबयान पेश किया गया है, सिवाय इस तथ्य के कि अभियोजन पक्ष जांच अधिकारी और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करने में विफल रहा है, जिससे बचाव पक्ष को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इस मामले को देखते हुए, हमारा मानना है कि जिन परिस्थितियों से दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे वर्तमान मामले में मौजूद नहीं हैं, इसलिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि अपीलकर्ताओं ने अपराध किया है।

22. इस प्रकार, पूरे मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता से उभर कर, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है और रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य का अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष अपराध के किए जाने को स्थापित करने के लिए ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद सबूत पेश करने में विफल रहा है और सभी उचित संदेहों से परे अपराध के किए जाने को साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह मानने में बड़ी गलती की है कि अपीलकर्ताओं द्वारा हत्या के आरोप को स्थापित करने के लिए भरोसेमंद, विश्वसनीय, विशिष्ट, पर्याप्त और ठोस गवाही है और बचाव पक्ष सभी उचित संदेहों से परे अपनी बेगुनाही साबित करने में सक्षम नहीं है।

23. इस प्रकार, तथ्यों और परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और पूर्वगामी कारणों से, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में ऐसे बाध्यकारी कारण हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त दोनों मामलों के अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाए।

24. तदनुसार, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि का निष्कर्ष, हमारी राय में, संधारणीय नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए, सत्र परीक्षण संख्या 817/2011 (खोदावंदपुर पी.एस. कांड संख्या 43/2011 से उत्पन्न) में अपर सत्र न्यायाधीश-II, जिला-बेगूसराय के विद्वान न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय दिनांक 06.09.2016 और सजा का आदेश दिनांक 08.09.2016 को रद्द किया जाता है। उक्त अपील के अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

25. अपीलकर्ता संख्या 1 मो. वसीम, जो हिरासत में है, को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो। जहां तक अपीलकर्ता संख्या 2 नूरजहां के संबंध में, वह पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसे जमानत बांड के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

26. तदनुसार, अपील यानी आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 1099/2016 को अनुमति दी जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

एस.एसबी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक हो